







# विचार

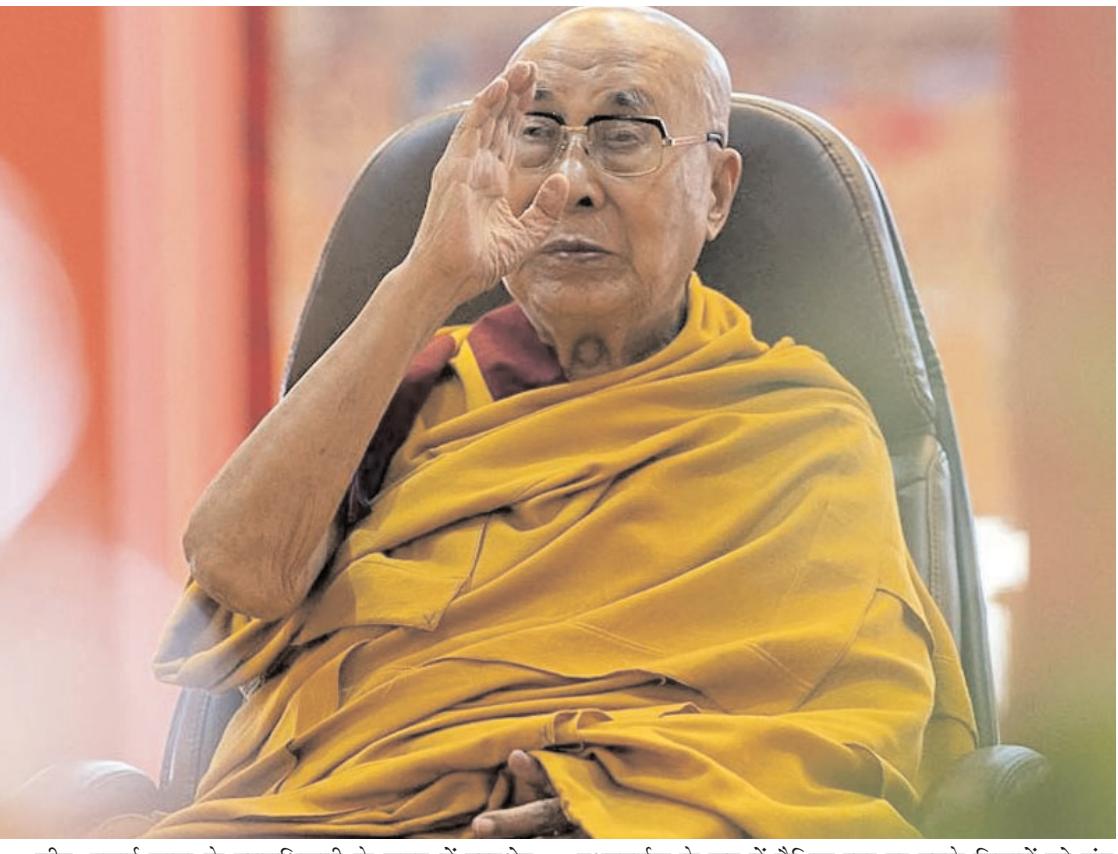
## कर्नाटक में कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गलती दोहरा रही है

कर्नाटक में कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज की थी। यह जीत केवल भाजपा को सत्ता से हटाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके साथ ही कांग्रेस ने यह संदेश भी दिया था कि यदि पार्टी एकजूट और ठोस नेतृत्व के साथ मैदान में उतरे तो वह भाजपा को धेर सकती है। लेकिन अब, कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और लगातार सांवर्जनिक रूप से सामने आने वाले मतभेदों ने सबाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस यहां पर वही गलती दोहरा रही है जो उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की थी? हम आपको याद दिला दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के विवाद कांग्रेस के लिए दीर्घांकित सिरदर्द बना रहा था। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सत्ता-सांझादारी को लेकर विवाद लगातार सामने आता रहा था। ऐसा ही वाक्या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच देखने को मिला था। ज्योतिरादित्य भाजपा में चले गये थे जिससे कमलनाथ की सरकार बीच में ही गिर गयी थी। तीनों ही राज्यों में मतभेद पार्टी मंच के बजाय मीडिया में उछलते रहे, जिससे भाजपा को सत्ता में आने का मौका मिल गया। इसी तरह कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है कि आलाकमान द्वारा समय रहते निर्णायक कदम नहीं उठाने के कारण टकराव बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की जोरदार जीत के बाद से ही यह स्पष्ट था कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। समझौते के तहत सिद्धारमैया को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन शिवकुमार खेमा इसे अंदर ही अंदर चुनौती दे रहा है। कर्नाटक में मत्रिमंत्री विस्तार की बात हो चाहे प्रशासनिक निर्णयों की बात हो या पिर रणनीतिक घोषणाओं की बात हो, सभी मामलों में दोनों नेताओं के बीच मतभेद लगातार उत्तराग्रह होते रहते हैं। इसके अलावा, कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी खुलेआम एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाज़ी कर रहे हैं। डीके शिवकुमार के समर्थक अक्सर उन्हें भावी मुख्यमंत्री कहकर प्रचारित करते हैं जो सिद्धारमैया समर्थकों को असहज करता है और इसके चलते दोनों और से बयानबाजी शुरू हो जाती है। हम आपको बता दें कि देश में सिर्फ तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और देखने में आ रहा है कि तीनों जगह पार्टी में कलह है। कर्नाटक के साथ ही हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी कांग्रेस नेता आपस में भिड़े हुए हैं लेकिन कर्नाटक की कलह कुछ ज्यादा ही उत्तराग्रह हो रही है। यही नहीं, कर्नाटक के विवाद को कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे द्वारा हाईकमान पर टालना दर्शाता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और सब कुछ ऊपर से ही मैनेज हो रहा है, तभी इस प्रकार का टकराव बना हुआ है। देखा जाये तो कांग्रेस इस समय देश में मुख्य विपक्षी पार्टी है इसलिए सबाल उठता है कि जब वह अपना घर ही नहीं संभाल पायी हो तो देश में मजबूत विपक्ष की भूमिका कैसे नियमायेगी? कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों को भी एकजूट रख पाने में विफल रही है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि केरल और हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सरकार में आना तय माना जा रहा था लेकिन अपने ही नेताओं के आपसी झगड़ों की बदौलत पार्टी सत्ता से बहुत दूर रह गयी थी। इससे सांबित होता है कि कांग्रेस को हमेशा अपनों ने ही लटाई है लेकिन फिर भी पार्टी गलतियों से सीख लेने को तैयार नहीं है। उधर, कर्नाटक में कांग्रेस के दोनों धुरंधर नेताओं के समीकरणों पर और करें तो आपको बता दें कि अत्यंत पिछड़े कुरबां समूदाय से आने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बड़े जनाधार बाले नेता हैं। वह सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं और उन्हें पता है कि चुनावों में भाजपा के जितागत समीकरणों को कैसे बिगाड़ा है। वर्ती प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आधिकारी-सामाजिक रूप से संपन्न वोकलिंग समूदाय से आते हैं। वह पुराने कांग्रेसी हैं, गांधी परिवार के विश्वस्त हैं और धनबल, बाहुबल के खिलाड़ी हैं। कई विधायक भी उनके साथ हैं लेकिन हाईकमान हर बार सिद्धारमैया के सिर पर हाथ रख देता है इसलिए उन्होंने हाल ही में कहा भी है कि मेरे पास समर्थन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

# दलाई लामा के घर पर चीन का साजिशपूर्ण हस्तक्षेप

**तिब्बत के आध्यात्मिक नेता एवं वर्तमान 14वें दलाई लामा, तेनजिन ज्यात्सो की जारी विवाद विवरण और भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति, मानवाधिकार और भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में भी**

**तिब्बत की संस्कृति से जुड़ा विषय है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति, मानवाधिकार और भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। चीन द्वारा इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि यह वैश्विक जनमत की भी अवहेलना है। इन स्थितियों में जारी विवाद विवरण और भारत के मसले पर भारत की भूमिका एक निर्णायक मार्गदर्शक के रूप में उभरती है और इसे दृष्टि में रखते हुए भारत ने दलाई लामा का पक्ष लिया है। ऐसा करने में कृष्ण भी अप्रत्याशित नहीं हैं। भारत शुरू से तिब्बतियों के अधिकार, उनके हितों और उनकी परंपराओं व मूल्यों के समर्थन में खड़ा रहा है। इन स्थितियों में जारी विवाद विवरण और भारत के मसले पर उसकी मनमानी नहीं चलेगी।**



चीन, दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, यह दावा करते हुए कि यह धार्मिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया का हस्ता है। हालांकि, दलाई लामा और तिब्बती समूदाय का कहना है कि यह अधिकार के बावजूद विवाद की अधिकारी नहीं है। उनका इशारा चीन की स्वतंत्रता के उल्लंघन है। चीन, 'स्वर्ण कलश' प्रणाली का उपयोग करके अपने पर्सेन्ट्री उम्मीदवारों को स्थापित करना चाहता है। चीन का कहना है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार उसे 'स्वर्ण कलश' प्रणाली के माध्यम से है, जो 1793 में किंग राजवंश के समय से चली आ रही है। इस प्रणाली में, सभावित उत्तराधिकारियों के नाम एक कलश में डाले जाते हैं और फिर एक नाम निकाला जाता है।

दलाई लामा के विवाद के धार्मिक नेता नहीं हैं, वे तिब्बती अस्तिता, स्वतंत्रता और अत्म-सम्मान के प्रतीक हैं। वर्तमान 14वें दलाई लामा, तेनजिन ज्यात्सो, 1959 में चीन की दमनकारी नीतियों के कारण असमर्थन के बावजूद रह रहा है। वह पुराने कांग्रेसी हैं, गांधी परिवार के विश्वस्त हैं और धनबल, बाहुबल के खिलाड़ी हैं। कई विधायक भी उनके साथ हैं लेकिन हाईकमान हर बार सिद्धारमैया के सिर पर हाथ रख देता है इसलिए उन्होंने हाल ही में कहा भी है कि मेरे पास समर्थन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

1959 में जब दलाई लामा को कम्युनिस्ट सरकार के दमन

के चलते भारत में शरण लेनी पड़ी थी, तब से हालात बिल्कुल बदल गए हैं— चीन बेहद ताकतवर हो चुका है और तिब्बत कमज़ोर। इसके बाद भी अगर तिब्बत का मसला जिंदा है, तो वजह है दलाई लामा। चीन इसे समझता है और इसी वजह से इस पद पर अपने प्रधान वाले किसी शब्द को बैठना चाहता है। चीन की योजना है कि जब वर्तमान दलाई लामा का देहांत हो, तो वह अपनी पसंद का एक 'दलाई लामा' घोषित करें, जिसे वैश्विक समूदाय भले ही स्थीकार करे, लेकिन चीन उसकी वहचान का जबरन वैधता प्रदान करे। यह एक राजनीतिक कठपुतली खड़ी करने जैसा है, जिसके उपरांत विवाद विवरण के बावजूद भी भारत और अपनी रणनीतिक स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा।

चीन ने तिब्बत की पहचान को मिटाने की हर सुप्रकार कोशिश कर रही है। दलाई लामा के पद पर दावा ऐसी ही एक और कोशिश है। उसकी वजह से यह मामला धर्म से आगे बढ़कर वैश्विक राजनीति का रूप ले चुका है, जिसका असर भारत और दूसरे देशों पर पड़े हैं, जहां तिब्बत के लोगों ने शरण ली है। भारत पर तो चीन लंबे समय से दबाव लगाता रहा है कि वह दलाई लामा को उसे सौंप दे। चीन और तिब्बत की लड़ाई भारतीय धर्म पर दशकों से चल रही है और नई दिल्ली-पैदिंग के बीच तानव का एक बड़ा कारण बनती रही है। दलाई लामा की घोषणा के अनुसार, उनका उत्तराधिकारी तिब्बत के बावजूद की भी हो सकता है— अनुचित हस्तक्षेप के बावजूद भी हो सकता है। भारत को इन दिनों में मौजूद अनुयायियों से कोई एक, तो यह तनाव और बढ़ सकता है। लेकिन, इसमें भारत के लिए एक बड़ा अकेला जैसा घटना में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और बाईं से लेकर व्यापार तक, हर जगह साह में रोडे अटकाने में लगा है।

धर्मशाला, जहां वर्तमान दलाई लामा रहते हैं, अब विश्व स्वर पर तिब्बती संस्कृत एवं बौद्ध परंपराओं का केंद्र बन गया है। भारत को इसके केंद्रों को आधिकारिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर इस धार्मिक स्वतंत्रता के लिए लंबाई भर करते हैं। अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ समन्वय स्थापित करके इस प्रकार वैश्विक समर्थन, कूटनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय तैयार करना चाहिए। अमेरिका भी पहले ही कह चुका है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी बौद्ध तिब्बती परंपराओ







